

11 09 23 / 2013 / DSE
26/05/13

1-1006/JS (copy)
27/5/13

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
मोर्चे ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110001

महोदय,

कृपया मुझे निम्नांकित सूचनाएं प्रदान करने का श्रम करें :-

1. निम्नांकित खण्डों/ संभागों में कार्यवाही के लिए विधि आयोग की आज तक कौन-कौन सी
की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, उन समस्त के विवरण प्रदान करें :

- क. Centre-State Division
- ख. Coordination Division
- ग. Human Rights Division
- घ. Internal Security Division
- ङ. Judicial Division
- च. Police Modernisation Division

2. विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या -29 Proposal To Include Certain Social And Economic
Offences In The Indian Penal Code-32 , Section 9 Of The Code Of Criminal
Procedure,--1898 Appointment Of Sessions Judges. Additional Sessions Judges And
Assistant Sessions Judges -36 ,Sections 497, 498 And 499 Of The Code Of Criminal
Procedure, 1898 -37 ,The Code Of Criminal Procedure. 1898 -41 , The Code of
Criminal Procedure 1898, -42 ,Indian Penal Code-43 , Offences Against The National
Security -48 , Some Questions Under The Code Of Criminal Procedure Bill. 141 ,1970
Need for amending the law as regards power of courts -152 , - Custodial Crimes -180 ,
Constitution of India and the Right to Silence -200 , Trial by Media-203 , Section -438
of the Code of Criminal -233 , Amendment of Code of Criminal Procedure Enabling
Restoration of Complaints -237 ,Compounding of (IPC) Offences-239 , Expeditious
Investigation and Trial of Criminal Cases Against Influential Public Personalities व -243
Section 498A IPC: Measures to check alleged misuse मंत्रालय के कित्त विभाग को कार्यवाही

के लिए प्राप्त हुई हैं

3. Prevention of Torture Bill पर राज्य सरकारों से प्राप्त अभिसर की प्रतियां

शुल्क भुगतान के लिए पोस्टल ऑर्डर संख्या 362698 भेजा जा रहा है अतः कृपया समायोजित करें और सूचना
प्रदान करने में शीघ्रता कर अनुरोधित करें।

दिनांक: 23 05 2013

भवनिष्ठ

मनीराम शर्मा

मनीराम शर्मा

रोडवेज डिपो के पीछे, नकुल निवास,
सरदारशहर जिला चुरू (राज)-331 403-7
ईमेल: maniramsarma@gmail.com

Dir (CCS)
Us (Coord)
Ds (HR)
Dir (JSI)
JS (Judicial)
Ds (PM)
27/5/13
Justice

AS(E)
SMT

3529/RSV/13
27/5

सज्जन श्री सतपाल चौहान, अपीलीय अधिकारी, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली - 110001

प्रथम अपील संख्या /

मनीराम शर्मा, नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे, सरदारशहर- जिला चुरू - अपीलार्थी
नामोपरि

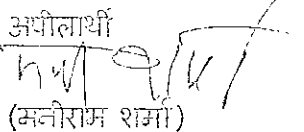
श्री जय प्रकाश अग्रवाल, जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली - 110001
प्रतिपक्षी

प्रार्थी अपनी पूर्व प्रासंगिक अपील दिनांक 23.01.13 के क्रम में निम्नानुसार निवेदन करता है :

1. यह है कि अपीलार्थी ने दिनांक 20.12.12 को उक्त अधिकारी को आवेदन कर कॉम्प्लेक्स सूचना की अपेक्षा की थी किन्तु प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त विलम्ब से दिनांक 15.05.13 को दिया गया जवाब असंतोषजनक है।
2. यह है कि अपीलार्थी ने अपने प्रासंगिक आवेदन से विधि आयोग की रिपोर्टों पर की गयी टिप्पणियों की सत्यापित प्रति तथा उक्त रिपोर्टों पर लिए गए निष्कर्षों को कब तक स्वप्रकटन के अंतर्गत वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा जानने की अपेक्षा की थी किन्तु अपीलार्थी को कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है।
3. यह है कि विधि आयोग की रिपोर्टों पर कानून बनाने से पूर्व उन पर विभाग द्वारा टिप्पणियाँ तैयार की जाती हैं और इन टिप्पणियों के पश्चात् ही कोई कानून बनाने अथवा नहीं बनाने का निर्णय लिया जाता है। विधि आयोग की समस्त अनुसंशाओं को प्रस्तुत रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि उन पर विभाग का अपना स्वतंत्र मत होता है। विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या -41 The Code of Criminal Procedure, 1898-42, Indian Penal Code -152 Custodial Crimes -203 Section 438 of the Code of Criminal Amendment of Code of Criminal Procedure Enabling Restoration of Complaints-237 तथा Compounding of (IPC) Offences -Section 498A IPC: Measures to check alleged misuse पर की गयी टिप्पणियों की प्रति देने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि जय कोई कानून बनाया जाता है तो यह स्वतः उपलब्ध हो जाता है किन्तु मैंने तो कानून निर्माण से पूर्व की गयी टिप्पणियों की मांग की है न कि कानून की। विधि आयोग की अनुसंशाओं से भिन्न कानून बनाने या कानून नहीं बनाने के निर्णय का मत/विचार एवं कारण का ज्ञान तो इन टिप्पणियों से ही हो सकता है और इसे जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है।
4. यह है कि अन्य रिपोर्टों के विषय में प्रत्यर्थी का तर्क है कि इन पर राज्य सरकारों का संतुष्ट परव्यक्ति सूचना है अतः इसे उनसे ही प्राप्त किया जा सकता है जबकि लोक प्राधिकारी के लोक कृत्य लोक दस्तावेज हैं और वे परव्यक्ति (Third party) सूचना की परिभाषा में नहीं आती हैं। फिर भी इन रिपोर्टों पर भी स्वयं विभाग की टिप्पणियाँ /मत / विचार सारजनिक किया जाना लोकतंत्र के हित में है।

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित समस्त सूचनाएँ किसी भी प्रावधान में दृष्ट प्राप्त नहीं होने से उसे स्पष्टरूप में तथा उसी प्रारूप में विंदु/स्तम्भवार निशुल्क दिलवाई जाएँ।

अपीलार्थी


(मनीराम शर्मा)

नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे

दिनांक 23.05.13

सरदारशहर-331403

RTI MATTER

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pt.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)

Reply of Sl No. 146

12/6/2013

New Delhi, Dated // June, 2013

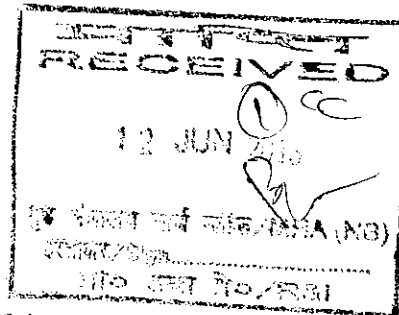
OFFICE MEMORANDUM

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005 by Shri Mani Ram Sharma.

Please find enclosed an RTI application dated 03.6.2013 alongwith its enclosures, received by the undersigned on 06.6.2013 on transfer from RTI Division, MHA.

2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the information sought by the applicant does not relate to this Division.

3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II), MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.



Rakesh Mittal
(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel.23092132

Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy to:

1. Shri Mani Ram Sharma, Behind Roadways Depot, Mukal Niwas, Sardarsahar, District - Churu, Rajasthan - 331405
2. Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Division, MHA, w.r.t. their Letter No.A-43029/1/2013-RTI dated 3.6.2013 for information.

1/6/13

12/6